भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 160

29 नवंबर, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन में गिरावट

160. डॉ. एल. हनुमंतय्या:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑटोमोबाइल और स्थावर संपदा क्षेत्र में धीमी माँग के कारण विगत पांच वर्षों में इस्पात उत्पादन में तीव्रतम गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कुल इस्पात उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात उत्पादन में गिरावट पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण है;

(घ) यदि हां, तो ऑटोमोबाइल और स्थावर संपदा क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ग): विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत में कच्चे इस्पात के उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**कच्चा इस्पात उत्पादन (मिलियन टन में)**
2016-17	97.94
2017-18	103.13
2018-19	110.92
2019-20	109.14
2020-21	103.54
2021-22 (अक्टूबर,2021 तक)	66.805
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)	

विगत तीन वर्षों के दौरान कुल तैयार इस्पात का क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:

घरेलू इस्पात खपत (मिलियन टन में)			
क्षेत्र	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**
भवन और निर्माण	42.9	43.4	41.0
अवसंरचना	24.4	25.1	23.8
ऑटोमोबाइल	9.3	8.8	8.4
इंजीनियरिंग और पैकेजिंग	21.8	22.0	20.9
रक्षा	0.4	0.9	0.8
कुल	**98.7**	**100.2**	**94.9**
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)			

(घ) और (ङ): सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), सभी के लिए आवास, जल जीवन मिशन, भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर का निर्माण और उड़ान पहल आदि जैसी परियोजनाओं के माध्यम से अवसंरचना के विकास पर विशेष जोर दिया है। मंत्रालय इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने और निर्माण/अवसंरचना एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में माँग में वृद्धि लाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि आवास एवं निर्माण, अवसंरचना, शहरी विकास, रेलवे, रक्षा, तेल एवं गैस, नागर विमानन, ग्रामीण विकास, कृषि, दुग्ध और खाद्य प्रसंस्करण आदि के हितधारकों को भी नीचे दिए गए ब्यौरानुसार शामिल कर रहा है:-

(i) फरवरी, 2020 में नई दिल्ली, मुंबई और भुवनेश्वर में अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई), जापान के सहयोग से जापानी विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(ii) दिनांक 30.06.2020 को भारतीय डेवलपर्स, बिल्डर्स, डिजायइनर्स, कन्सलटेंट, फेब्रिकेटर्स, आईआईटी के अकादमीशियन और इस्पात उत्पादकों के साथ देश में, विशेषकर निर्माण क्षेत्र में, इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया।

(iii) दिनांक 18.8.2020 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के साथ आवास निर्माण क्षेत्र में इस्पात उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वेबिनार का आयोजन किया गया।

(iv) लंबी विस्तृति (लांग स्पैन) (30 मीटर, 35 मीटर एवं 40 मीटर) वाले इस्पात-आधारित पुलों के डिजाइन के विकास हेतु आईएनएसडीएजी, आईआईटी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) और उद्योग विशेषज्ञों की एक समिति का गठन।

(v) अनुमानित लागत के साथ इस्पात की संरचना वाले आवास विन्यासों के मानकीकृत डिजाइन और ले-आउट, जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) वाले घरों में अपनाया गया है, को विकसित करने हेतु आवास और निर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का भी गठन किया गया है, जिसमें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एचयूए), कौशल विकास मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, बीआईएस, सीपीडब्ल्यूडी, तकनीकी संस्थाओं (आईआईटी) और उद्योग जगत के सदस्य शामिल हैं।

(vi) भारत में ऑटोग्रेड इस्पात के प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले घरेलू निर्माण एवं खरीद की संभावना को समझने के लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (ईईपीसी), कई ऑटोमोबाइल कंपनियों एवं भारतीय इस्पात उत्पादकों को शामिल करना।

****